(126)

संख्या-562/XVIII(II)/12-03(125)/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून ।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 8 मई , 2012

विषयः-उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के भवन निर्माण हेतु 0.410 है0 भूमि समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0-126/12 ए-6 (2011-14) दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित ग्राम सौडा सरोली परगना परवादून जिला देहरादून के खाता संख्या-266 के खसरा नं0 543 ड़ रकबा 0.0510,खसरा नं0-549 रकबा 0.3500 कुल रकबा 0.4010 है0 भूमि, वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-2-2002 में निहित प्राविधानों एवं समाज कल्याण विभाग,उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अनुसार, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओमप्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0संख्या–569 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।